



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 994]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2018/फाल्गुन 21, 1939

No. 994]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2018/PHALGUNA 21, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

का.आ. 1114(अ).—अंतरराज्यिक नदी महानदी और उसकी घाटी नदी से सम्बंधित जल विवाद (जिसे इसमें इसके पश्चात विवाद कहा गया है।) न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए ओडिशा सरकार से अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन अनुरोध प्राप्त हुआ है;

और ओडिशा सरकार, ने उच्चतम न्यायालय में 2017 की मूल वाद संख्या 1 फाइल की थी और उक्त न्यायालय ने तारीख 23 जनवरी, 2018 के आदेश में केंद्रीय सरकार को एक जल विवाद अधिकरण का गठन करने का निदेश दिया था;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित 'महानदी जल विवाद अधिकरण' नामक एक जल विवाद अधिकरण का गठन करती है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

1. न्यायमूर्ति श्री ए. एम. खानविलकर,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
2. न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन,
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. न्यायमूर्ति श्रीमती इन्दरमीत कौर कोचर,
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

-अध्यक्ष;

-सदस्य;

-सदस्य.

[फा. सं. 4/1/2016-बी.एम.]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,

यू.पी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2018

S.O. 1114(E).—Whereas a request has been received under section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) from the Government of Odisha to refer the water dispute regarding the inter-state river Mahanadi, and the river valley thereof (hereinafter called the said dispute), to a Tribunal for adjudication;

And whereas, the Government of Odisha filed an Original Suit No.1 of 2017 in the Supreme Court and the said Court in its order dated the 23rd January, 2018 directed the Central Government to constitute a Water Disputes Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the aforesaid Act, the Central Government hereby constitutes a Water Disputes Tribunal called 'The Mahanadi Water Disputes Tribunal', with headquarters at New Delhi for the adjudication of the said dispute consisting of the following members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, namely:-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Mr. Justice A.M. Khanwilkar,
Judge of the Supreme Court of India | —Chairman; |
| 2. | Dr. Justice Ravi Ranjan,
Judge of the Patna High Court | —Member; |
| 3. | Mrs. Justice Indermeet Kaur Kochhar,
Judge of the Delhi High Court | —Member. |

[F. No. 4/1/2016-BM]

By Order and in the Name of President of India,

U. P. SINGH, Secy.